नईदुनिया



रेजरपे आईपीओ को मिली सेबी की मंजूरी, 6,500 करोड़ तक जुटाएगी कंपनी

नई दिल्ली

देश की प्रमुख फिनटेक कंपनी रेजरपे को आखिरकार शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से हरी झंडी मिल गई है। कंपनी का लक्ष्य इस आईपीओ के जरिए 5,500 से 6,500 करोड़ रुपए तक जुटाना है और इसकी लिस्टिंग 2027 की पहली तिमाही में होने की उम्मीद है।

2027 की पहली तिमाही में लिस्टिंग संभव, वित्त वर्ष 25 में राजस्व बढ़ा, लेकिन घाटा भी हुआ

यह कदम फिनटेक सेक्टर में रेजरपे की बढ़ती साख और निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है, हालांकि कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में मजबूत राजस्व वृद्धि के साथ-साथ घाटा भी दर्ज किया गया है। सेबी की मंजूरी और वैल्यूएशन की स्थिति रेजरपे को हाल ही में सेबी से ड्राफ्ट आईपीओ दस्तावेजों पर अंतिम टिप्पणियां मिली थीं, जिसके बाद कंपनी अब अपनी लिस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ सकती है।

कंपनी ने जून में गोपनीय तरीके से ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस जमा किया था। बाजार में रेजरपे का संभावित वैल्यूएशन करीब 5 अरब डालर (लगभग 49,000-50,000 करोड़ रुपए) आंका जा रहा है, जो 2021 में मिले 7.5 अरब डालर के वैल्यूएशन से कम है। आईपीओ में 2,700 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि मौजूदा निवेशक आफर फार सेल के जरिए अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेच सकेंगे।

एक्सिस कैपिटल, जेपी मार्गन, सिटी और कोटक महिंद्रा कैपिटल इस आईपीओ के प्रमुख सलाहकार हैं। बाजार का रुख और रेजरपे की रणनीति रेजरपे ऐसे समय में आईपीओ ला रही है, जब नई टेक कंपनियों की कमाई, ग्रोथ और वैल्यूएशन पर निवेशक कड़ी नजर रख रहे हैं।

वालमार्ट समर्थित फोनपे जैसी कंपनियों ने भी बाजार की अनिश्चितता के कारण अपनी आईपीओ योजना टाल दी थी। 2014 में स्थापित, रेजरपे कारोबारियों को आनलाइन, आफलाइन और क्रास-बार्डर पेमेंट सहित विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी ने अपने आफलाइन पेमेंट कारोबार की रणनीति में बदलाव किया है, जिससे लागत घटाने और मुनाफा बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, कंपनी ने मई 2025 में अमेरिका से भारत मुख्यालय स्थानांतरित कर रिवर्स फ्लिप प्रक्रिया पूरी की है, जिससे भारतीय बाजार में लिस्टिंग का रास्ता साफ हो गया।

न्यूज ब्रीफ

नवंबर में मिल रहे नई होंडा कार पर शानदार ऑफर



नई दिल्ली। नवंबर 2026 में नई होंडा कार पर होंडा सिटी, तीसरी जनरेशन होंडा अमेझ और दूसरी जनरेशन अमेझ पर आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। होंडा सिटी पर सबसे ज्यादा 1.86 लाख रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं। वहीं अमेझ के दोनों मॉडल पर भी हजारों रुपये की बचत का मौका है। बता दें कि ये ऑफर 30 नवंबर 2026 तक मान्य हैं। नवंबर के लिए सामने आए मॉडल-वाइज ऑफर्स में सामने आया है कि होंडा सिटी पर 1.86 लाख रुपये तक के फायदे मिल सकते हैं। तीसरी जनरेशन होंडा अमेझ पर 66,800 रुपये तक और दूसरी जनरेशन अमेझ पर 57,600 रुपये तक की बचत बताई गई है। साथ ही इसमें ध्यान रहे कि ये अधिकतम फायदे हैं । हर वेरिएंट या ग्राहक को इतनी ही छूट मिले यह जरूरी नहीं है। इस महीने होंडा सिटी पर सबसे ज्यादा बचत का मौका मिल रहा है। वहीं नई अमेझ खरीदने वालों को 66,800 रुपये तक के फायदे मिल सकते हैं। साथ ही पुरानी मतलब दूसरी जनरेशन अमेझ पर भी 57,600 रुपये तक के ऑफर बताए गए हैं। इन फायदों में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बेनिफिट और कॉर्पोरेट ऑफर जैसे अलग-अलग लाभ शामिल हो सकते हैं। लेकिन हर मॉडल के लिए इनका पूरा ब्रेकडाउन उपलब्ध नहीं है। इसलिए खरीदारी से पहले डीलर से लिखित जानकारी लेना बेहतर रहेगा।

टीडी पावर सिस्टम्स ने सितंबर तिमाही में रिकार्ड तोड़ प्रदर्शन किया, कंपनी का मुनाफा 105.6 फीसदी बढ़कर 123.74 करोड़ रुपए



मुंबई। विद्युत उपकरण बनाने वाली कंपनी टीडी पावर सिस्टम्स ने सितंबर तिमाही में रिकार्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। कंपनी ने 12 नवंबर को जारी नतीजों में मुनाफा और राजस्व दोनों में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की। इन शानदार नतीजों और मजबूत वृद्धि संभावनाओं के चलते एसबीआई सिक्योरिटीज ने खरीदारी की सलाह दी है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्राफिट सालाना आधार पर 105.6 फीसदी बढ़कर 123.74 करोड़ रुपए हो गया। इसी अवधि में आपरेशंस से रेवेन्यू 85.9 फीसदी बढ़कर 841.31 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आपरेटिंग परफार्मेंस भी सुधरा एबिटा 109.6 फीसदी बढ़कर 174 करोड़ रुपए रहा। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 65 फीसदी अंतरिम डिविडेंड (0.65 रुपए प्रति शेयर) की घोषणा भी की है, जिसके लिए 18 नवंबर को रिकार्ड डेट तय की गई है। शेयर बाजार में कंपनी के प्रदर्शन की बात करें तो, इस साल यह शेयर 88 फीसदी चढ़ चुका है। एसबीआई सिक्योरिटीज ने 732 रुपए का टारगेट प्राइस देते हुए इसे खरीदने की सलाह दी है।

मुंबई में सीएनजी फिर महंगी, 91.50 रुपए प्रति किलो पहुंचा दाम, साल में आठवीं बढ़ोतरी, जनवरी से अब तक 11 रुपये महंगा हुआ ईंधन



नई दिल्ली। मुंबई और आसपास के इलाकों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं, जिसने वाहन चालकों की चिंता बढ़ा दी है। महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने रविवार, 15 नवंबर को सीएनजी के दाम में 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा किया, जिसके बाद अब इसका खुदरा मूल्य 91.50 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है। ये नई दरें 14 नवंबर की आधी रात से लागू हो गई हैं। यह इस साल की आठवीं वृद्धि है। जनवरी में 80.50 रुपये प्रति किलोग्राम रही सीएनजी की कीमत में अब तक कुल 11 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है, जो लगभग 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है। इस वृद्धि से मुंबई मेट्रोपालिटन रीजन (एमएमआर) में लगभग 12.93 लाख सीएनजी वाहनों, जिनमें आटो-रिक्शा, टैक्सी और निजी गाड़ियां शामिल हैं, के मालिकों का ईंधन खर्च बढ़ जाएगा। महानगर गैस लिमिटेड ने कीमतों में बढ़ोतरी की वजह गैस खरीदने की बढ़ती लागत, घरेलू प्राकृतिक गैस के कम आवंटन और आयातित रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर बढ़ती निर्भरता को बताया है। कंपनी के अनुसार, मध्य पूर्व में जारी संकट और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव ने उनकी इनपुट लागत को काफी बढ़ा दिया है।

सीएजी का फर्टिलाइजर सब्सिडी का अभा परफॉरमेंस ऑडिट शुरू

नई दिल्ली

कैग (सीएजी) ने फर्टिलाइजर सब्सिडी का अखिल भारतीय परफारमेंस आडिट शुरू किया है। परफारमेंस आडिट का मुख्य उद्देश्य 169 जिलों में सब्सिडी वाले यूरिया के कथित डायवर्जन की जांच करना है। इसमें फर्टिलाइजर को देश के बाहर भेजे जाने की आशंका भी शामिल है।

यह आडिट 2027 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। सरकार सब्सिडी वाले यूरिया पर सालाना 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करती है। कुछ जिलों में यूरिया की खपत राष्ट्रीय और राज्य के औसत से कहीं ज्यादा है, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सीएजी यूरिया सब्सिडी ढांचे की मांग और कार्यकुशलता का आकलन करेगा; यही इस आडिट के दायरे में भी शामिल है। जिन 169 जिलों में कथित डायवर्जन की जांच होनी है, उनमें से 149 को सीएजी ने शुरुआत में ही उनके खपत पैटर्न के आधार पर चुना था, जो राज्य और राष्ट्रीय औसत से अधिक था।

बाद में, केंद्र सरकार की सिफारिश पर 20 और जिलों को इसमें जोड़ा गया, ताकि उनके खपत पैटर्न की भी जांच की जा सके। यह आडिट फर्टिलाइजर की आवाजाही, परिवहन व्यवस्था, माल ढुलाई सब्सिडी और इससे जुड़ी निगरानी और नियंत्रण प्रणाली की पड़ताल करेगा। इस व्यापक आडिट में विभिन्न सरकारी विभागों, जैसे जीएसटी नेटवर्क, कृषि मंत्रालय, रेलवे आदि का सहयोग लिया जाएगा। ये विभाग फर्टिलाइजर नियंत्रण प्रणाली और नियामकों की कार्यकुशलता के आकलन में आडिटरों की मदद करेंगे। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ई-वे बिल के आधार पर यूरिया के डायवर्जन की आशंका जताई थी, क्योंकि यह पाया गया कि ट्रक तय रास्ते के बजाय दूसरे रास्तों से जा रहे थे या कई जगहों पर रुक रहे थे।

एक संसदीय समिति ने भी यूरिया के डायवर्जन, खासकर सीमावर्ती जिलों में, को लेकर चिंता जताई थी। अधिकारियों ने बताया कि यूपी, राजस्थान, पंजाब और बिहार के सीमावर्ती जिलों से सब्सिडी वाले यूरिया को दूसरी जगहों पर भेजे जाने (डायवर्जन) की खबरों ने इस बात पर भी संदेह पैदा कर दिया है कि कहीं इसे देश के बाहर तस्करी करके तो नहीं भेजा जा रहा है।



जमाखोरी पर केंद्र की स्ट्राइक! दालों के स्टाक का साप्ताहिक खुलासा अनिवार्य, नियमित रूप से स्टाक की सही जानकारी दें और बाजार में आपूर्ति को सुचारू बनाए रखें

नई दिल्ली। देश में दालों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने और बाजार में कृत्रिम किल्लत व जमाखोरी पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला लिया है। अब सभी प्रकार की दालों के लिए अनिवार्य स्टाक घोषणा की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत, दालों के पूरे आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े सभी हितधारकों को नियमित रूप से अपने स्टाक की जानकारी सरकार को देनी होगी, ताकि बाजार में पारदर्शिता लाई जा सके और उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा हाल ही में बुलाई गई एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस बैठक में देश के सभी स्टाकिस्ट, मिलर्स, आयातकों, थोक और खुदरा विक्रेताओं के साथ-साथ बड़ी रिटेल चेन को भी प्रत्येक सप्ताह अपने दालों के स्टाक की विस्तृत जानकारी साझा करना अनिवार्य होगा। विभाग के अधिकारियों ने दाल मिलर्स, आयातकों, ट्रेडर्स, डीलर्स और बड़ी रिटेल चेन के प्रतिनिधियों के साथ करीब 3 घंटे तक मैराथन चर्चा की, जिसमें बाजार में दालों की उपलब्धता और खुदरा कीमतों की गहन समीक्षा की गई। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कारोबारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित रूप से स्टाक की सही जानकारी दें और बाजार में आपूर्ति को सुचारू बनाए रखें ताकि कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। सरकार का मानना है कि इस साप्ताहिक खुलासे से बाजार में दालों की वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी।

यूरिया की अत्यधिक खपत के लिए जिन जिलों की जांच की जा रही है, उनमें सबसे ज्यादा 37 जिले यूपी में हैं। इसके बाद बिहार और तमिलनाडु में 16-16 जिले, और पंजाब तथा गुजरात में 14-14 जिले शामिल हैं। बाद में जांच के दायरे में लाए गए 20 जिले कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से हैं। भारत में यूरिया की कुल खपत सालाना लगभग 400 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है।

6 राज्यों में शुरू होगी इलेक्ट्रिक कैब सर्विस



नई दिल्ली

इलेक्ट्रिक कैब सर्विस देने वाली कंपनी ग्रीन एसएम की योजना अपनी आल-इलेक्ट्रिक कैब सर्विस को छह भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचाने की है। वर्तमान में ग्रीन एसएम दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद में अपनी सेवाएं दे रही है। वहीं अब कंपनी की नजर चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों पर है। इस विस्तार से ग्राहकों को इलेक्ट्रिक कैब का विकल्प मिलने के साथ स्थानीय ड्राइवरों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। ग्रीन एसएम ने जून 2026 में भारत में अपनी शुरुआत दिल्ली-एनसीआर से की थी।

कंपनी ने यहां वीनफास्ट लीमो ग्रीन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ ग्रीन एसएम लीमो सर्विस शुरू की। इसके बाद हैदराबाद में भी परिचालन शुरू किया गया। वहीं कंपनी का दावा है कि भारत में शुरुआती पांच महीनों के दौरान उसने 15 लाख से ज्यादा राइड पूरी की हैं।

ऐसे में अब ग्रीन एसएम चेन्नई और बेंगलुरु में अपनी सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी स्थानीय प्रशासन और पार्टनर्स के साथ मिलकर जरूरी परिचालन व्यवस्था तैयार कर रही है। कंपनी ने बताया है कि उसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में एग्रीगेटर लाइसेंस मिल चुके हैं। इन अनुमतियों के आधार पर वह संबंधित राज्यों में ऐप के जरिए कैब सर्विस चला सकती है। लेकिन लाइसेंस मिलने का मतलब यह नहीं है कि सभी शहरों में सर्विस शुरू हो गई है। चेन्नई और बेंगलुरु में लान्च की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। साथ ही ग्रीन एसएम का कहना है कि विस्तार के दौरान मौजूदा टैक्सी ड्राइवरों को भी अपने नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

कंपनी उन्हें ट्रेनिंग, बेहतर कमाई के अवसर और वेलफेयर सपोर्ट देने की योजना बना रही है। ग्रीन एसएम ने उन रिपोर्ट्स को गलत बताया है जिनमें दावा किया गया था कि कंपनी 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया लेती है। कंपनी ने बताया है हर शहर में स्थानीय परिवहन नियमों और सरकार द्वारा तय किराये का पालन किया जाएगा। ग्राहक बुकिंग कन्फर्म करने से पहले ऐप पर अपनी यात्रा का किराया देख सकेंगे। ग्रीन एसएम की एंट्री से बेंगलुरु के कैब बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है।

डाकघर एमआईएस, हर माह पाएं निश्चित आय



नई दिल्ली। शेयर बाजार के जोखिम से बचकर सुरक्षित और नियमित आय कमाने की तलाश कर रहे निवेशकों के लिए डाकघर की मंथली इनकम स्कीम (एमआईएस) एक आकर्षक विकल्प बनकर उभरी है। यह केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं में से एक है, जिसे जमा पूंजी से हर महीने नियमित आमदनी चाहने वालों के लिए बनाया गया है। पोस्ट आफिस मंथली इनकम स्कीम (एमआईएस) की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक बार पैसा जमा करने के बाद हर महीने ब्याज के रूप में नियमित आमदनी होती है। इतना ही नहीं, यह बैंक फिक्स्ड डिपाजिट (एफडी) से भी अधिक ब्याज दर प्रदान करती है। जो लोग अपनी जमा पूंजी पर सुरक्षित और निश्चित रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। निवेशक इस योजना में निवेश कर हर महीने 9250 रुपए तक की संभावित ब्याज आय प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता मजबूत होती है।

माइक्रोसाफ्ट की ग्लोबल सेवाएं बहाल, 24 घंटे बाद मिली राहत

आउटलुक, टीम्स, माइक्रोसाफ्ट 365 जैसी प्रमुख सेवाएं प्रभावित

नई दिल्ली

माइक्रोसाफ्ट ने घोषणा की कि उसकी सभी कंज्यूमर और एंटरप्राइज सेवाएं, जो 24 घंटे से अधिक समय से एक वैश्विक तकनीकी रुकावट के कारण बाधित थीं, अब पूरी तरह से बहाल कर दी गई हैं। इस आउटेज ने दुनिया भर के लाखों उपयोगकर्ताओं को प्रभावित किया, जिन्हें आउटलुक, टीम्स और माइक्रोसाफ्ट 365 कोपायलट जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँचने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तकनीकी दिग्गज माइक्रोसाफ्ट ने अपनी सभी उपभोक्ता और उद्यम सेवाओं की पूर्ण बहाली की पुष्टि की है, जिससे 24 घंटे से अधिक समय तक चली एक वैश्विक तकनीकी बाधा समाप्त हो गई है। कंपनी के सर्विस स्टेटस पेज पर सभी सेवाएं बहाल का संदेश पोस्ट किया गया, जो दुनिया भर में लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए राहत की बात है। यह समस्या गुरुवार को शुरू हुई और शुक्रवार तक कई देशों में व्यवसायों, सरकारी एजेंसियों और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करती रही। आउटलुक, टीम्स, माइक्रोसाफ्ट 365 कोपायलट, शेयरपाइंट आनलाइन और अन्य क्लाउड-आधारित सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाइयों के कारण ईमेल सेवाएं बाधित हुईं, वर्चुअल मीटिंग्स पर असर पड़ा और महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा आई। माइक्रोसाफ्ट ने इस वैश्विक आउटेज के लिए अपने ग्राहकों और साझेदारों से गहरा खेद व्यक्त किया है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह एक तकनीकी समस्या थी, जिसका साइबर हमले या एआई एजेंट्स से कोई लेना-देना नहीं था। यह खराबी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने (नेटवर्क कैपेसिटी अपग्रेड) के दौरान आई, जो हाल ही में किए गए एक नेटवर्क बदलाव के बाद सामने आई। कंपनी ने कहा कि मूल समस्या को ठीक कर दिया गया है। सेवाओं की बहाली के बारे में बताते हुए, माइक्रोसाफ्ट ने कहा कि मांग के बड़े स्तर को देखते हुए, उन्होंने धीरे-धीरे सेवाएं बहाल कीं और हर चरण पर स्थिरता की जांच की। हालांकि इसमें थोड़ा अधिक समय लगा, लेकिन इससे सेवाओं को पूरी तरह से स्थिर तरीके से बहाल करने में मदद मिली।



सबसे ज्यादा बिकने वाली टाप-25 कारों की लिस्ट में मारुति वैगनआर शीर्ष पर

नई दिल्ली

देश के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली टाप-25 कारों की लिस्ट में मारुति वैगनआर ने सभी लोकप्रिय माडलों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह सूची बीते महीने अक्टूबर में जारी हुई है।

इस सूची के अनुसार, मारुति वैगनआर ने टाटा पंच और नेक्सन जैसे माडलों के साथ-साथ मारुति ब्रेजा, बलेनो, डिजायर और अर्टिगा को भी पछाड़ दिया। इस लिस्ट के टाप-10 में मारुति सुजुकी के 7 माडल शामिल रहे, जबकि टाप-25 में कुल 11 मारुति माडल ने अपनी जगह बनाई। महिंद्रा के 5 और टाटा व हुंडई के 3-3 माडल भी लिस्ट में शामिल रहे।

टाप पर रही वैगनआर की शुरुआती कीमत महज 4.99 लाख रुपए है, और सीएनजी से इसका माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है।



इसके बेस वैरिएंट में भी 6 एयरबैग मिलते हैं, जो इसकी सुरक्षा और किफायतीपन को मजबूत करते हैं। अक्टूबर 2026 में मारुति वैगनआर की 23,747 यूनिट्स बिकीं, जो अक्टूबर 2025 में बिकी 18,970 यूनिट्स के मुकाबले 25प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्शाती है।

दूसरे स्थान पर मारुति ब्रेजा रही, जिसकी 22,436 यूनिट्स बिकीं और इसे 86प्रतिशत की शानदार वायओवाय वृद्धि हासिल हुई। टाटा नेक्सन 21,966 यूनिट्स के साथ तीसरे नंबर पर रही, जिसमें मामूली 1प्रतिशत की गिरावट देखी गई।

अन्य प्रमुख माडलों में मारुति बलेनो (20,919 यूनिट्स), मारुति डिजायर (20,649 यूनिट्स) और मारुति अर्टिगा (20,641 यूनिट्स) शामिल रहे, जिन्होंने टाप-10 में अपनी जगह बनाए रखी। टाटा पंच ने भी 20,525 यूनिट्स की बिक्री के साथ 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

ईंधन कीमतों में राज्यों के बीच भारी अंतर बरकरार, कहीं पेट्रोल 100 रुपये पार है, तो कहीं 115 रुपये प्रति लीटर

नई दिल्ली। देश भर के वाहन चालक हर सुबह पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों पर नजर रखते हैं। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के उतार-चढ़ाव के बीच, तेल कंपनियों ने रविवार भी दाम अपडेट किए हैं, जिनमें शहरों और राज्यों के बीच बड़ा अंतर दिख रहा है। कहीं पेट्रोल 100 रुपये पार है, तो कहीं 115 रुपये प्रति लीटर से भी अधिक। इसकी मुख्य वजह जीएसटी से बाहर होना और राज्यों का अलग-अलग वैट है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर है, जबकि मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे शहरों में कीमतें काफी ऊंची हैं, जहां पेट्रोल 111 रुपए से 116 रुपए के बीच बिक रहा है। राज्यों के स्तर पर तेलंगाना, मध्य प्रदेश और केरल में ईंधन सबसे महंगा है। यह भारी अंतर मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए अलग-अलग वैट के कारण है, क्योंकि ईंधन अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है। इन दामों को तय करने में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, डालर के मुकाबले रुपये की स्थिति, राज्य सरकारों का वैट, परिवहन खर्च और डीलर कमीशन जैसे कई कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिलहाल, कीमतों में कटौती की कोई स्पष्ट घोषणा नहीं है। आगे के दाम वैश्विक कच्चे तेल की चाल, रुपये-डालर विनिमय दर और सरकारी टैक्स नीतियों पर ही निर्भर करेंगे।